साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 07-13 नवंबर , 2022, वर्ष-8, अंक-31

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्राकृतिक आपदाओं के बीच बीत रहा 2022, नौ माह में रोजाना हुई दुर्घटनाएं

खेती पर टूटा प्राकृतिक कहर

» जनवरी से सितंबर तक किसी न किसी तरह की प्राकृतिक घटनाएं दर्ज की गईं

» प्रतिदिन आपदा झेलने से भारत में पिछले नौ माह में 2,755 की मौत

» 18 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद, 4 लाख घर नष्ट, 70 हजार पशुओं की मौत

अरविंद मिश्र। भोपाल

भीषण गर्मी, मूसलाधार बारिश, चक्रवात और पहाड़ों पर लैंड स्लाइड... 2022 भारत के लिए लगातार कहर बनकर टूट रहा है। देश में लोगों ने वर्ष 2022 के नौ माहों में लगभग प्रतिदिन किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा को झेला है। इसी का नतीजा है कि इस दौरान 2,755 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, इस दौरान मध्यप्रदेश सहित देशभर में 18 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और चार लाख घर बर्बाद हुए, जबकि लगभग 70,000 पशु मारे गए। यह चौंकाने वाला खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा किए गए एक नए आकलन में सामने आया है। यह अतिविषम मौसमी चरम घटनाएं एक जनवरी से 30 सितंबर, 2022 के बीच दर्ज की गईं हैं।

देश में साल के शुरू होने से सितंबर तक हर दूसरे दिन किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी घटना की वजह से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या हिमाचल प्रदेश (359) में सबसे अधिक है। जबकि मध्य प्रदेश और असम में 301 लोगों की मौत दर्ज की गई है। मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम की घटनाओं के साथ सबसे अधिक (198 और 195 दिन) दर्ज किए गए है। अगर जानमाल के नुकसान की बात करें तो मध्य भारत 887 मौतों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पूर्व और उत्तर पूर्व भारत हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब तक 783 मौतें हुई हैं।

तीन माह सबसे अधिक बारिश

भारत ने 1901 के बाद से 2022 में अपना सातवां सबसे नम जनवरी माह दर्ज किया। मार्च भी 121 वर्ष में अब तक का सबसे गर्म और तीसरा सबसे सूखा रहा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत ने 121 वर्षों में सबसे गर्म और सबसे शुष्क जुलाई देखा। इस क्षेत्र ने 2022 में अपना दूसरा सबसे गर्म अगस्त और चौथा सबसे गर्म सितंबर भी दर्ज किया। देश के 30 राज्यों में आकाशीय बिजली और तूफान से 773 लोगों की जानें गईं। मानसून के तीन माह जून से अगस्त तक के प्रत्येक दिन देश के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक वर्षा होने के संकेत मिले।

लू ने 45 लोगों की जान ली

लू ने 45 लोगों की जान ले लीं, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं है। यह उत्तर भारत में लोगों पर लंबे समय तक उच्च तापमान का प्रभाव है। किसानों से लेकर श्रमिकों ने भीषण गर्मी का सामना किया। अच्छी खबर यह है कि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्य कम थी। देश में 95,066 हेक्टेयर क्षेत्रों को नष्ट करने वाले चक्रवातों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल दो लोगों की जानें गईं।

वर्ष 2022 के नौ माह में भारत ने प्रतिदिन एक आपदा झेली। इसमें गर्म और सर्द हवाओं से लेकर चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं शामिल थीं। इन आपदाओं में 2,755 जानें गईं, 18 लाख हेक्टेयर फसल का क्षेत्र प्रभावित हुआ, 4,16, 667 से अधिक घर नष्ट हुए, लगभग 70,000 पशु मारे गए। आपदाओं के हर दूसरे दिन होने वाली घटना के मामले में मध्य प्रदेश में ऐसे दिनों की संख्या अधिक थी।

सुनीता नारायण,
महानिदेशक, सीएसई

देश में असम एक ऐसा राज्य है जहा सबसे अधिक घर टूटने और जानवरों की मौत के मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद दक्षिण भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसे 82 दिनों तक मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं बात खेती की करें तो कही देर से तो कहीं जरुरत से ज्यादा बारिश और सूखे जैसे हालातों के चलते फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

किरण पांडे, कार्यक्रम निदेशक, पर्यावरण संसाधन इकाई सीएसई

खाद वितरण पर शिवराज ने लगाई अफसरों की क्लास

» मंत्री के साथ रात साढ़े दस बजे सीएम हाउस बुलाए अफसर

» पन्ना जिले में खाद वितरण केन्द्रों से खाद बांटने में गड़बड़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

बोवनी के मौसम में खाद के लिए परेशान हो रहे किसानों की शिकायत सीएम तक पहुंच गई। पन्ना जिले में सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान को जानकारी मिली कि कुछ खाद वितरण केन्द्रों से खाद बांटने में गड़बड़ी की जा रही है। यह शिकायत संज्ञान में आते ही सीएम ने भोपाल पहुंचकर सहकारिता विभाग के अफसरों को रात साढ़े दस बजे सीएम हाउस तलब कर लिया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के साथ अन्य विभागीय अफसर सीएम हाउस पहुंचे जहां मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को खाद की वितरण व्यवस्था की निगरानी कर दुरूस्त रखने के निर्देश दिए।

जिलों में खाद की व्यवस्था रखें दुरुस्त

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जिलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ जगहों से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था में तत्काल सुधार का किया जाए। पन्ना जिले के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री निवास में शिवराज ने सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और प्रबंध संचालक मार्कफेड के साथ प्रदेश में खाद व्यवस्था के बारे में चर्चा कर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरस्त रखने के निर्देश दिए।

-केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला

देश के किसानों को सस्ती दारों पर मिलेगी खाद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों के हित मे बड़ा फैसला लिया है। किसानों को अब खाद सस्ती दरों में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में किसान हित में बड़ा फैसला लिया गया है। अब लगभग आधी कीमत पर किसानों को मिलेगा खाद। केंद्रीय कैबिनट ने फास्फेटिक और पोटाश उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित नई दरों को मंजूरी देते हुए कैबिनेट सब्सिडी के लिए 51875 रुपए मंजूर कर दी है। अब उर्वरकों की लागत पहले से कम हो जाएगी। यह रबी सीजन 2022-23 जो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लिए मंजूर की है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश जैसे विभिन्न पोषक तत्वों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की प्रति किलोग्राम दरों के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब नाइट्रोजन 98.02 रूपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस 66.65 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश 23.65 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर 6.12 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती दरों में उपलब्ध होगा।

51,875 करोड़ की सब्सिडी को मिली मंजूरी

इलाज के लिए दवा सहित जरूरी हर सुविधाएं, वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज भी रखा

हरदा की गौशाला में खुला गौ आईसीयू वार्ड

भोपाल। जागत गांव हमार

देश प्रदेश में गायों पर राजनीति के बीच हरदा जिले ने एक सराहनीय पहल की है। यहां गायों के लिए आईसीयू वॉर्ड बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये संभवत: देश का पहला गौ आईसीयू है। इसमें गंभीर हालत में बीमार गायों को इलाज किया जाएगा। इस आईसीयू में गायों के बेहतर इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हरदा जिले में गोपाष्टमी के मौके पर गौवंश के लिए नई पहल की गयी है। जिले में गौशाला में गायों के लिए आईएसीयू वार्ड बनाया गया है। इसे गौ चिकित्सा आईसीयू कक्ष नाम दिया गया है। यहां गंभीर स्थिति में लाए गए गौवंश का इलाज किया जाएगा। गायों के लिए बने अनोखे आईसीयू में दवाओं सहित जरूरत की सभी चीजें जुटाई गयी हैं। गौ आईसीयू में एसी लगाया गया है और ठंड से बचाव के लिए हीटर भी है। हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गौशाला में गौमाता का पूजन कर आईसीयू कक्ष का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि हरदा कृषि मंत्री का गृह जिला भी है।

गायों का आईसीयू

अभी तक आपने अस्पतालों में इंसानो के इलाज के लिए बने आईसीयू वार्ड देखे होंगे, लेकिन हरदा जिले में गौ वंश संरक्षण और उनके बचाव के लिए दयोदय गौशाला में गौ वंश के लिए आईसीयू कक्ष बनाया गया है। पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लेस आईसीयू में गौ वंश के लिए जरूरी जीवन रक्षक दवाएं रखी गयी हैं। साथ ही वैक्सीन सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज भी है। गायों के बैठने के लिए नीचे रेत बिछाई गयी है। गौ शाला में मौजूद डॉक्टर दुर्घटना में घायल या गंभीर बीमारी से पीड़ित गाय का इलाज इस आईसीयू में कर सकेंगे। साढ़े सात लाख रुपए की लागत से आईसीयू कक्ष को बनाया गया है।

अपने आप में बेहतरीन आईसीयू गौशाला से जुड़े सुयोग सोनी ने बताया कि आईसीयू में गायों का वैक्सिनेशन भी किया जा सकेगा। जिले की सभी गौशालाओं में इस तरह की सुविधाएं जुटाई जाएंगी। दयोदय गौशाला के अध्यक्ष अनूप जैन ने कहा गौशाला में गोबर से गौ काष्ठ बनायी जाती हैं। इस गौकाष्ठ का उपयोग अंत्येष्टि में भी करते हैं। साथ ही गौ मूत्र और गोबर से जैविक घोल बनाकर किसानों को दिया जा रहा है। जिससे गाय संरक्षण और प्रकृति दोनों बचे।

अभी बैंकों में विभागीय अधिकारी ही प्रशासक बन संभालेंगे कमान

डिफाल्टर किसानों के कारण अधर में पड़े सहकारी समितियों के चुनाव

मध्यप्रदेश के 50 लाख किसान चुनते हैं अपना प्रतिनिधि

भोपाल। जागत गांव हमार

सहकारी समितियों के चुनाव अभी भी नहीं होंगे। अभी तक विभिन्न कारणों से चलते टलते आ रहे चुनाव अब डिफाल्टर किसानों के कारण अधर में पड़ गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में में 50 लाख से ज्यादा किसान सवा चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव करते हैं। इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल का चुनाव होता है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से लेकर अपेक्स बैंक तक के चुनाव खटाई में पड़ गए हैं। इसके पीछे बड़ा कारण कमलनाथ सरकार में सभी किसानों का कर्ज माफी नहीं हो पाना है। लाखों किसान वर्तमान में डिफॉल्टर हैं और ये किसान चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके चलते सरकार सहकारी चुनाव टाल रही है। वहीं राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों से मतदाता सूची मांगी है जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि कितने किसान वोट कर सकते हैं। फिलहाल बैंकों में प्रशासक प्रथा लागू रहेगी।

प्रदेश में पैक्स के चुनाव दस साल से अधिक समय से अटके हैं। जिसके कारण करीब 30 जिला सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल तथा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सका है। सहकारी चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। अदालत के आदेश पर राज्य सरकार ने राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश में सहकारी और अन्य संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। हर माह तीन हजार संस्थाओं और सहकारी समितियों के चुनाव कराए जा रहे हैं लेकिन पैक्स के चुनाव अटके हैं। प्रदेश में करीब साढ़े चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) हैं। सबसे पहले इन्हीं समितियों का चुनाव होता है। इसमें किसान ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन, जानकारी सामने आई है कि लाखों किसान डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर किसान चुनाव नहीं लड़ सकता।

25 लाख किसानों को कर्जमाफी का इंतजार

कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने संबंधी आदेश जारी किया था। पहले चरण में 50 हजार रुपए तक का कर्ज माफ करने के लिए कांग्रेस सरकार ने दो हजार करोड़ का प्रावधान किया था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में बताया कि 20 लाख 23 हजार 136 प्रकरणों में 7108 करोड़ रुपए का ऋण माफ हुआ। ये 25 लाख से अधिक किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। ये किसान पैक्स का चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पैक्स के चुनाव कराए गए तो कोई भी डिफॉल्टर किसान कर्ज माफी का फायदा नहीं मिलने को लेकर कोर्ट जा सकता है और ऐसे में चुनाव में रोक लगने की संभावना ज्यादा है। यही कारण है कि सरकार सहकारी चुनाव को आगे बढ़ाना चाहती है।

पांच साल में चुनाव कराने का प्रावधान

सहकारी अधिनियम में पांच साल में सहकारी समितियों के संचालक मंडल का चुनाव कराने का प्रावधान है। नियमानुसार यह चुनाव फरवरी 2018 में हो जाने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह चुनाव नहीं कराए गए थे। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और चुनाव टल गए। इसके बाद कमल नाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू कर दी, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाए। मार्च 2020 में सत्ता परिवर्तन के बाद कोरोना महामारी के कारण चुनाव की स्थिति नहीं बनी। तब से ही सहकारी समितियों के चुनाव टलते आ रहे हैं।

किसानों का ब्याज भरेगी सरकार

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि डिफाल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने दो लाख के माफी के चक्कर में पैसा नहीं भरा, डिफॉल्टर हो गए। वहीं कमलनाथ का कहना है कि उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया। दूसरे चरण में कर्ज माफ करने की कार्रवाई चल ही रही थी कि सरकार चली गई।

डिफाल्टर किसानों को अलग करके सदस्यता सूची तैयार होगी

समितियों से ऋण लेने वाले किसान लगभग 56 लाख हैं। इनमें से चालीस लाख मतदान में हिस्सा लेने की पात्रता रखते हैं, क्योंकि डिफाल्टर किसानों को मतदान में हिस्सा लेने की पात्रता नहीं होती है। इनके नाम अलग करके सदस्यता सूची तैयार होगी। इसके आधार पर पहले समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। इसमें से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो संचालक मंडल का चुनाव कराएंगे। इनमें से अपेक्स बैंक के लिए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो बैंक के संचालक मंडल का चुनाव करेंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर रीवा कृषि कॉलेज में हुई एकता दौड़

रीवा। कृषि कॉलेज रीवा के कृषि अधिष्ठाता प्रो. एसके पयासी के निर्देशन में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉ. मनीषा द्विवेदी और विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग के डॉ. अखिलेश कुमार, कृषि कॉलेज, रीवा के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं द्वारा एकता दौड़ का आयोजन के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ का आयोजन हुआ जिसमें अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. अखिलेश कुमार ने कहा जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, उस समय लगभग 565 रियासतें थीं जो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुकी थीं और उस समय भारत संघ में नहीं थीं। अपनी काबिलियत या सैन्य क्षमता का इस्तेमाल करते हुए सरदार पटेल ने भारत के संघ के साथ इन राज्यों को एकजुट करने का एक सराहनीय काम किया। डॉ. मनीषा द्विवेदी ने बताया की सरदार वल्लभभाई पटेल भारत की सिविल सेवाओं के संरक्षक संत और भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक और कर्मचारियों ने भाग लिया।

पर्यटन बढ़ाने ग्रामीणों को पढ़ा रहे मेजबानी का पाठ

प्रदेश के 10 गांवों से रिस्पांसबिल टूरिज्म की शुरुआत

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनजीवन से पर्यटकों को जोड़ने की पहल पर्यटन विभाग ने शुरू की है। गांव के रहन-सहन से लेकर यहां की संस्कृति, कला, खानपान से जुड़ी जीवनशैली से पर्यटकों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने रिस्पांसबिल टूरिज्म मिशन चलाया है। इसमें मध्यप्रदेश के लगभग 100 गांवों को चिन्हित किया है, जहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों को पर्यटकों के रहने, उनके खाने-पीने से लेकर ग्रामीण परिवेश से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग इन्हें प्रशिक्षित भी कर रहा है। गांव की महिलाओं को इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाने का काम होगा। इसमें महिलाओं द्वारा महिला पर्यटकों के साथ रहकर उन्हें गांव की संस्कृति, जीवनशैली और खानपान से अवगत कराया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस योजना में मध्य प्रदेश को छह भागों में बांटा है। इसमें मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, महाकोशल, बघेलखंड और नर्मदापुरम शामिल हैं। इन क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है।

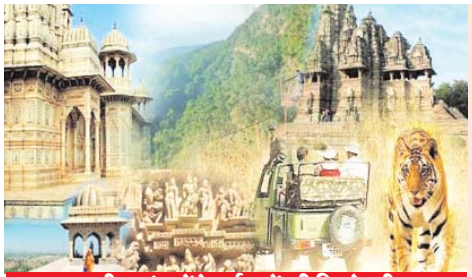

ग्रामीण संभालेंगे पर्यटकों की जिम्मेदारी

- गांव में पर्यटकों को रुकने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्रामीणों के जिम्मे होगी।
- यहां पर उनके लिए वाहन से लेकर क्षेत्रीय भ्रमण भी ग्रामीणजन ही कराएंगे।
- ग्रामीण महिलाओं की मदद से महिला पर्यटकों को गांव के खानपान और धर्म से जोड़ा जाएगा।
- यहां की कला, संगीत, नृत्य से जोड़ने का जिम्मा भी ग्रामीण महिलाओं का ही होगा।
- इस कामों के लिए उनकी शुल्क तय होगा और वे प्रशिक्षण लेकर बेहतर काम करेंगे।

रिस्पांसबिल टूरिज्म के माध्यम से गांवों में रहने वालों में यह भावना विकसित करना है कि पर्यटन हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम पर्यटकों के लिए गांव में रहने, उनके खानपान से लेकर उन्हें ग्रामीण जनजीवन से जोड़ने का काम ग्रामीणों से ही करा रहे हैं। इसमें सफलता भी मिली है। पहले चरण में हमने जिन गांवों को लिया, वहां पर पर्यटकों ने ठहरने के बाद अच्छे फीडबैक दिए।

-डॉ. मनोज सिंह, संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड

दूसरे चरण में जोड़े जाएंगे 60 गांव

प्रदेश के 10 गांवों से रिस्पांसबिल टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। इन गांवों को अभी प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र जैसे खजुराहो, ओरछा, पचमढ़ी, कान्हा, बांधवगढ़ से लिया गया है। यहां पर पर्यटक भी आना शुरू हो गए हैं और उनसे इस मिशन का बेहतर फीडबैक भी मिला है। इसके बाद विभाग दूसरे चरण में प्रदेश के 60 गांवों को लेगा। इन गांवों में लोगों को जोड़कर उनके घर में ही पर्यटकों के रुकने, खाने की व्यवस्था की जाएगी। इन ग्रामीणों को पर्यटन हमारी जिम्मेदारी से जोड़कर उनके आर्थिक हालात को सुधारने का प्रयास होगा।

किसान अब परंपरागत खेती छोड़ विकल्प तलाश रहे हैं। पारंपरिक फसलों के अलावा सब्जियों, फूलों और फलों की खेती की ओर तेजी से रुझान बढ़ रहा है। गुना के दो किसानों ने एक पहल की और आज परंपरागत से कई गुना ज्यादा लाभ कमा रहे हैं। वे गेंदे की खेती कर रहे हैं। इन दिनों फसल पूरी तरह तैयार है।

25 हजार की लागत में एक लाख का मुनाफा

एमपी के गेंदे की प्रयागराज तक डिमांड

-गुना के किसानों ने बताया खेती का तरीका

गुना। जागत गांव हमार

जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी दूर गढ़ा गांव। यहां के किसान मुकेश कुशवाह और कमल सिंह कुशवाह ने 5 साल पहले पारंपरिक खेती छोड़ एक बीघा में गेंदे के फूल की खेती शुरू की। पहले ही साल अच्छा मुनाफा हुआ। अब वह करीब 5 बीघा जमीन में फूलों की खेती कर रहे हैं। वह गुना, अशोकनगर समेत भोपाल, ग्वालियर और प्रयागराज तक फूल भेज रहे हैं। हर साल इसमें प्रति बीघा 25 से 30 हजार रुपए खर्च कर सालाना 4 से 5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। गेंदा ऐसा फूल है, जिसमें सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके फूलों को सालभर में 10-12 बार तोड़ सकते हैं।

यह है गेंदा लगाने की प्रक्रिया

किसान मुकेश कुशवाह ने बताया कि गेंदे की फसल के लिए जून के महीने में खेत तैयार करना शुरू कर देते हैं। पहले देसी खाद और सुपर खाद को मिक्स कर डाला जाता है। इसके बाद खेत की गुड़ाई करनी होती है। 8-10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर क्यारी (बेड) बनाई जाती हैं। यह करीब 3.5 फीट चौड़ाई की बनाई जाती हैं। एक से दूसरी क्यारी की दूरी करीब 3 फीट रखी जाती है। अब बारी आती है बीज डालने की। बीज डालने के 15 दिन बाद क्यारी को मिट्टी से भर दिया जाता है। हर 10 से 12 दिन में सिंचाई की जाती है। पौधे थोड़े बड़े होने पर दोनों ओर रस्सी लगाई जाती है, जिससे पेड़ झुके नहीं और टेढ़ा न हो।

ढाई महीने में फसल तैयार

बीज लगाने से लेकर फसल तैयार होने तक में ढाई महीने का समय लगता है। बीज लगाने के 20-30 दिन में पौधे तैयार होते हैं। पौधे लगाने के बाद करीब 30 दिन में फूल आना शुरू हो जाते हैं। हर एक हफ्ते में फूल तोड़ने पड़ते हैं। एक पौधे पर 50 से ज्यादा फूल लगते हैं। एक बार तोड़ने पर फिर उसमें कलियां लगने लगती हैं।

सबसे कठिन प्रक्रिया माला बनाना

मुकेश बताते हैं कि फसल तैयार होने के बाद लगातार इसे बाजार में भेजना होता है। शाम को फूल तोड़कर सुबह मंडी में ले जाया जाता है। यहां नीलामी के जरिए फूल बिकता है। माला बनाकर भी भेजना होता है। भोपाल, ग्वालियर और इलाहाबाद सीधा फूल ही जाता है। 30 किलो का पैकेट बनाकर फूल भेजते हैं। फूल की डिमांड गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाती है। नवरात्र में भी डिमांड ज्यादा रहती है। सबसे ज्यादा मांग दिवाली के समय होती है।

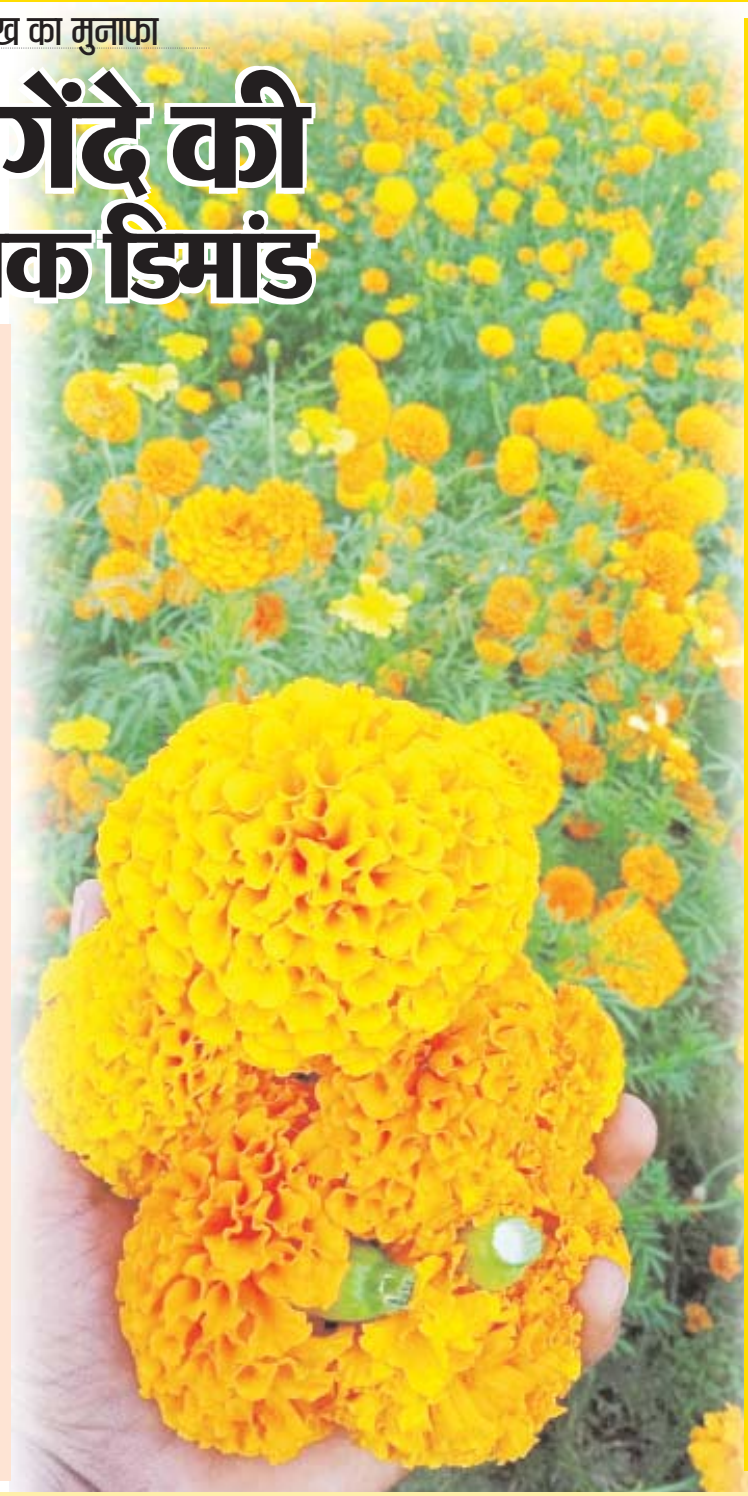

लागत 20 हजार, मुनाफा एक लाख

एक बीघा जमीन पर खेत तैयार करने से लेकर बीज, लेबर और फसल में पानी देने में 25 से 30 हजार रुपए खर्च आता है। वहीं, सालाना 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। गेंदे के बीज अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से आते हैं। 500 रुपए से लेकर 2.5 हजार तक का बीज आता है। 10 ग्राम का पैकेट आता है। इसमें करीब एक हजार बीज निकलते हैं। इसमें से 700-800 बीज ही पनपते हैं। वहीं, बाजार में एक किलो फूल 60, 70 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक बिक जाते हैं। डिमांड के हिसाब से भी रेट मिलती है। ऑफ सीजन में एक माला थोक में 6-10 रुपए तक बिकती है। वहीं, सीजन में 15 रुपए तक भी कीमत पहुंच जाती है।

सबसे ज्यादा मांग दिवाली पर

सबसे मुश्किल काम भी दिवाली के समय माला बनाने का होता है। क्योंकि एक ही दिन भारी मांग होने से सप्लाई ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए धनतेरस के दिन से ही फूल तोड़ना शुरू कर देते हैं। दिवाली के एक दिन पहले से माला बनाना शुरू करते हैं। रात-रात भर काम करना होता है। ज्यादा लेबर की जरूरत भी इन्हीं 2 दिन ही पड़ती है।

फूल की किस्म

अफ्रीकन गेंदा: इन किस्में के फूलों के पौधों की ऊंचाई 60-80 सेंटीमीटर तक होती है। यह विभिन्न आकार, रंगों और आकर्षक वाले होते है।

हाजारिया: हाजारिया गेंदा के पौधे की अधिक ऊंचे नहीं होती है। इसकी ऊंचाई कम से कम 30 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक होती है।

गोपाष्टमी से भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया था गो चराना

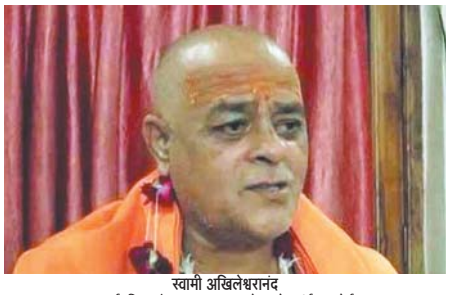

स्वामी अखिलेश्वरानंद
कार्यपरिषद के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गो-संवर्धन बोर्ड

भारत में पर्वों को मनाने की एक दीर्घकालीन परम्परा है। भारतीय काल गणना के ज्योतिषीय आधार भारतीय ऋषि मुनियों की पञ्चाङ्ग संरचना और उसके अनुसार तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, वार, घटी, पल, ग्रह, योग आदि हैं। अतीत में घटी घटनाएँ, पर्वों का आकार और स्वरूप धारण करती हैं। आधुनिक ज्योतिष विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वर्ष का कलेण्डर भी इसी आधार पर सुनिश्चित होता है तथा तदनुसार कार्यक्रम होते हैं और एक पर्वों की श्रृँखला चल पड़ती है।

पांच हजार वर्ष पूर्व द्वापर युग में द्वापर के महानायक, तत्कालीन युगपुरूष श्रीकृष्ण ने भारतीय पर्वों की एक परम्परा का शुभारम्भ अपनी लीलाओं के माध्यम से किया। ये पर्व अधिकांश प्रकृति, पर्यावरण एवं प्रकृति के विभिन्न उपादानों से सम्बंधित हैं। जैसे पर्वतों का संरक्षण, पेड़-पौधों, वनस्पतियों का रक्षण और औषधीय गुण वाले पौधों का रोपण। नदी-संरक्षण के साथ नदियों में प्रदूषण की रोकथाम। गायों का रक्षण, गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का महत्व स्थापित कर पञ्चगव्य की उपयोगिता को स्थापित करना। गोपालन, कृषि के महत्त्व को स्थापित करना। जंगल में गायों को घास चराने ले जाना, गो-चारण की वृत्ति को हर युग में प्रासंगिक बनाये रखने के लिये स्वयं गोचारण का व्रत धारण करना। धरती को हरीतिमा से परिपूर्ण रखने के लिये वन्य विहार करना इत्यादि। ये सभी विधायें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी द्वापर युग में प्रासंगिक थीं! तभी से विभिन्न पर्वों की परम्परा भारतवर्ष में अक्षुण्ण है।

गोवर्धन पूजा, गोवत्स द्वादशी, गोपाष्टमी, हल षष्ठी (बलराम जयंती) ये कुछ भारतीय पर्व ऐसे हैं जो आज भी जनमानस में रचे बसे हैं। इन पर्वों को मनाये जाने की धारा को और तीव्र करना, इन्हें युगानुकूल, समसामयिक बनाना आज के समय की आवश्यकता है।

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रतिवर्ष गोपाष्टमी के रूप में मनाये जाने की परम्परा है। द्वापर युग नायक श्री कृष्ण आठ

वर्ष की अल्पायु के थे, जब उन्होंने अपने माता-पिता से गायों को चराने जंगल जाने की जिद् की और अपने बाल सखाओं गोप-गोपालों को संगठित कर सभी से गोचारण करने हेतु आग्रह किया। बाल हठ के सामने श्रीकृष्ण के माता-पिता और श्रीकृष्ण के बालसखाओं के माता-पिताओं को गायों को घास चराने जंगल जाने के अभियान को स्वीकृति देना पड़ी।

उस तिथि को प्रात:काल शुभ मुहूर्त में बृज मण्डल के ग्रामीण क्षेत्र की गायों और गो-संतानों को एकत्रित कर बृज मण्डल के बालकृष्ण के समस्त बालसखाओं का एकत्रीकरण हुआ। बृजमण्डल के आबाल, वृद्ध, नर-नारी सभी ने श्री कृष्ण-बलदाऊ (श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी) के नेतृत्व में एक वृहद् गो-संगोष्ठी कर गाय के महत्त्व को रेखांकित किया। गोबर-गोमूत्र, पञ्चगव्य की महिमा का निरूपण किया तथा गो-वंश के सृष्टि-संरक्षण में योगदान को जनमानस में स्थापित किया। तदुपरांत घर के बड़े-बुजुर्गों ने श्रीकृष्ण बलराम सहित गोप-गोपालकों का तिलक किया, पुष्पमालाओं से गोपालकों के कण्ठ सुशोभित किये। लकुटि-कमरिया सभी को दी, गोपालकों की आरती उतारी,गायों का भी तिलक लगाकर पूजन कर उन्हें गो-ग्रास समर्पित कर जंगल की ओर विदा किया।

द्वापर युग की गोचारण व्रत की यह घटना भारतवर्ष के इतिहास की अमर तिथि हो गई। भारतीय पर्व परम्परा का यह एक प्रेरणास्पद अमर पाथेय हो गया। हम इसे आज भी प्रासंगिक बनाये रखना चाहते हैं। अत: मध्यप्रदेश की समस्त गो-शालाओं में, गोपालकों के घरों में गायों का आज के दिन पूजन हो और गाय के युगानुकूल, समसामयिक महत्व को आधुनिक युग के विकसित भौतिक विज्ञान की कसौटी में कस कर उसके वैज्ञानिक विश्लेषण को जनमानस में स्थापित करना समय की अनिवार्य आवश्यकता सिद्ध की जाये। इस पर्व के माध्यम से हमारा प्रयास है, इसे सफल, सार्थक और प्रभावी बनाना।

व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन समय की मांग

डॉ. संदीप नानावटी
प्राध्यापक एवं प्रमुख
पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू, म.प्र.

दुग्ध उत्पादन के मामले में मप्र का पूरे देश में सातवां है, यहां इस क्षेत्र में कुछ कर पाने की गुंजाइश ज्यादा है। वर्तमान में 250 मि.लि./दिवस /व्यक्ति दूध की आवश्यकता अभी भी अपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में सुनियोजित ढंग से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित करना आवश्यक हो गया है। ताकि हम परिश्रम, कम लागत, कम पशुओं एवं न्यूनतम भूमि के उपयोग में हम ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादित कर सकें। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिये पशु पालन के चार प्रमुख आधार स्तम्भ काम करते हैं। पिछले एक दशक में पशुपालन गांवशहरों में प्रविष्ट हो चुका है। नवयुवकों का एक बढ़ा तबका इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट हुआ है।

बैंकों की उदारवादी ऋण नीति से भी संगठित डेयरी फार्म निरंतर बढ़ रहे हैं। यद्यपि पारम्परिक पशुपालन में भवन निर्माण की इतनी अहमियत नहीं दी गई लेकिन अब साबित हो चुका है कि सफल दुग्ध उत्पादन के लिये आवास व्यवस्था उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि पोषण एवं चिकित्सा प्रबंधन जैसे अन्य तथ्य। यदि पशुपालक भाई पशुओं की आवास व्यवस्था में थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर भवन निर्माण करें तो दुग्ध उत्पादन का व्यवसाय फायदे मंद साबित हो सकता है। पशुओं के आवास निर्माण में पशुपालकों को निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकताओं एवं पूंजी के अनुरूप आवास व्यवस्था का प्रबंध करना चाहिए।

स्थान का चुनाव 2.पशुशाला का आकार 3. पशुओं को बांधने की विधि 4.पशुशाला का निर्माण 5. पशुशाला की ऊंचाई 6.पशुशाला में प्रकाश की व्यवस्था 7.जल निकास की व्यवस्था 8.हवा के आने जाने की व्यवस्था 9.पशुशाला की सफाई

स्थान का चुनाव

पशुशाला ऊंची जगह पर होनी चाहिए। पषुषाला को उत्तम जल निकास वाली जगह पर बनाना अत्यंत आवयष्क है यदि बड़ी पशुशाला बनानी हो तो स ?क के किनारे बनाना चाहिए। इससे बाजार तक आने जाने में सुविधा होती है। दाना चारा आदि बाजार से सरलता से लाया जा सकता है। दूध और अन्य दुग्ध पदार्थों को बाजार एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने में आसानी होती है। पशुशाला बड़े-बड़े कारखानों के पास नहीं होना चाहिए। पशुषाला में बिजली व पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पषुओं को पक्के भवन में रखा जाय तो बहुत अच्छा। ऐसे में पशुओं का वर्षा,ठंड एंव गर्मी से बचाया जा सकता है तथा साफ-सफाई भी बनी रहती है।

पशुशाला के पास गोबर गैस संयंत्र प्लांटद्ध भी लगाया जा सकता है। उर्जा विकास निगम संयंत्र बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी देता है। गोबर गैस के लिए कम से कम दो पशुओं का गोबर रोज लगता है। इससे खाद, बिजली और गैस मिलती है।

पशुशाला का आकार: कम पशुओं के लिए छोटी व अधिक पशुओं के लिए बड़ी पशुशाला बनाई जा सकती है। यदि पशुयों की संख्या 20 से ज्यादा हो तो दो कतारों वाली पशुशाला बनाई जा सकती है। दो पशुओं के बीच 5 फीट की दूरी रहती है। 20 पशुओं को बांधन के लिये 1500 वर्गफीट का भवन पर्याप्त होता है। पशुशाला का फर्ष पक्का हो, सीमेंट या एस्बेस्टास की हो तथा ताजी हवा के लिये पशुशाला पांच फीट की दीवार के उपर खुली रहे। इसमें लोहे की जालियॉ भी लगाई जा सकती है।

गौशाला से उत्सर्जी पदार्थों तथा गोबर मूत्र के निकास की उचित व्यवस्था होना चाहिए अन्यथा ये रोगों का कारण बनेंगी। पशुशाला की गोबर व मूत्र की नालियां, चौड़ी व ढालदार होनी चाहिए। इन नालियों द्वारा गोबर, मूत्र बिछावन, भूसा आदि खाद के गड्ढों में सरलता से जा सकते हैं। इन नालियों व गड्ढों को सीमेन्ट से पक्का बनाना चाहिए। नालियां 9 से 12 इंच चौड़ी व 3 इंच गहरी होनी चाहिए। इन नालियों का ढाल खाद के गड्ढों तक होना चाहिए।

दो पंक्तियों वाली बड़ी पशुशाला की लम्बाई पूर्व पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए। लम्बाई पूर्व पश्चिम की दिशा में रखने से पशुओं को हवा का दबाव कम रहता है। जिससे उनको तेज हवा बहने के समय असुविधा नहीं होती है। साथ में रोषनी भी पर्याप्त मात्रा में पशुओं को उपलब्ध रहती है।

कहा जा सकता है-पशुशाला का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया जाना जरूरी है। इसमें पशुओं के लिए छाया, प्रकाश एवं हवा आने की व्यवस्था हो। उनके खड़े रहने तथा बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो। पशुशाला की सफाई प्रतिदिन ठीक तरह से करनी चाहिए। जिससे पशुओं की सेहत अच्छी रहती है इससे उनकी कार्यक्षमता एवं दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और हम कम खर्च में अधिक लाभ मिल सकेगा।

पक्षियों में विटामिन की कमी, समस्या और निदान

पक्षियों/मुर्गियों में विटामिन की कमी एक आम समस्या है। दाने में पर्याप्त पोषक तत्व न होने से विटामिन की कमी हो जाती है। विभिन्न विटामिन की कमी को अनेक लक्षणों के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।

विटामिन दो प्रकार के होते हैं।

-वसा में घुलनशील (ए, डी, के)
-जल में घुलनशील (बी काम्प्लेक्स)

» डॉ. डॉ. अर्पिता श्रीवास्तव
» डॉ. नीरज श्रीवास्तव
» डॉ. बालेयवरी दीक्षित
» डॉ. राजीव रंजन
» डॉ. अमित कुमार झा
» डॉ. स्वतंत्र कुमार सिंह
- पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा, (मप्र)

(1) वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए यह विटामिन आंखों के लिए त्वचा, नम स्थानों व मुर्गियों की बढ़त के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसकी कमी से बढ़त में कमी, कमजोरी व अण्डा उत्पादन कम हो जाता है।

विटामिन डी- यह विटामिन कैल्शियम के उपयोग हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से भूख कम लगती है। बढ़ोत्तरी में कमी, अचानक मृत्यु हो जाती है। पैरों में कमजोरी रहती है। पैर टेढ़े हो जाते है। अण्डे का खोल पतला रहता है। अण्डा उत्पादन कम हो जाता है।

विटामिन ई-यह मस्तिष्क के विकास एवं एंटीआक्सीडेंट के समान कार्य करता है। इसकी कमी से मासपेशियॉं कमजोर हो जाती है, केजी चिक रोग हो जाता है।

विटामिन के- यह रक्त का थक्का बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तथा रक्त चोट आदि में लगातार बहता रहता है।

विटामिन बी1-यह भूख बनाये रखने के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन है। तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से भूख कम लगती है। शरीर की बढ़त रूक जाती है। कभी-कभी मुर्गियों की मृत्यु तक हो जाती है। विटामिन बी2 रू दाने में इसकी कमी से मुर्गियों की बढ़त रूक जाती है अण्डा उत्पादन कम जो जाता है। कर्ल टो पैरालिसस हो जाता है।

विटामिन बी12-यह पंखों की बढ़त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से एनीमिया, कमजोर मुर्गी व भ्रूण अवस्था में मृत्यु हो जाना जैसी समस्या होती है।

फोलिक एसिड-यह मुर्गियों की बढ़त के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से अण्डा उत्पादन मे कमी, पेरासिस व लकवा हो जाता है।

पेन्टाथोनिक एसिड रू यह मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी अच्छी बढ़त के लिए, अत्यंत आवश्यक है। कमी से मुह में छाले हो जाते है। खुजली हो जाती है। किडनी व लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पायरीडोक्सिन, कोलिन विटामिन भी बढ़त के लिए आवश्यक है इनकी कमी से मुर्गियों में झटके आते हैं, अण्डा उत्पादन कम होता है। फेटी लिवर की समस्या हो जाती है। उपरोक्त सभी विटामिन मुर्गियों की उचित बढ़त बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, पशुपालक को दाने पानी में इनकी उचित मात्रा प्रदान करते रहना चाहिए अन्यथा उत्पादन की कमी से पशुपालक को अधिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

देवास की आर्टिशन कंपनी को दिया आर्डर

देवास के बांस से डेनमार्क की कंपनी बनाएगी पवन ऊर्जा

भोपाल।

डेनमार्क ने बांस से बनी इन पंखुड़ियों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी देवास की आर्टिशन कंपनी की टीम को रिसर्च के दौरान दी गई है। डेनमार्क की कंपनी ने देवास की इस कंपनी के साथ 100 पंखुड़ियां लेने का करार भी कर लिया है। जल्द ही पंखुड़ियां तैयार कर डेनमार्क सप्लाई की जाएंगी। आर्टीशन दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज में बांस का इस्तेमाल कर रही है।

यह कंपनी घर बनाने से लेकर फर्नीचर बनाने तक हर काम में बांस का इस्तेमाल करती है। यहां बने कई उत्पाद विदेशों तक भेजे जा रहे हैं। इस शानदार प्रयोग से ना सिर्फ पूरे मध्यप्रदेश का नाम रोशन होगा, बल्कि इससे एक और फायदा होने वाला है। ये काम लगभग 2000 महिलाओं को रोजगार भी देगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह अनुकरणीय पहल होगी। कंपनी के सीईओ देवोपम मुखर्जी ने बताया है कि वह 50 एकड़ जमीन पर एक फैक्ट्री का निर्माण करवाएंगे और अब तक 1000 एकड़ भूमि में वह जंबू बांस रोप चुके हैं। देवास में बांस से बनी पंखुड़ियों (ब्लेड) से अब डेनमार्क में पवन ऊर्जा बनाई जाएगी। यहां बनने वाली पंखुड़ियां हल्की होने के साथ 40 साल मजबूत भी रहेंगी, जबकि फाइबर से बनी पंखुड़ियां चार साल में ही खराब हो जाती हैं। बांस से बनी ब्लेड की लागत भी कम है। इसीलिए डेनमार्क ने इनके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हाल ही में देवास की बांस उत्पादक आर्टिशन कंपनी की टीम को डेनमार्क में रिसर्च के दौरान सफलता मिली है। डेनमार्क की कंपनी ने देवास की कंपनी के साथ 100 पंखुड़ियों का करार किया है। इनकी सप्लाई भी जल्द होगी।

बांस का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी

टेक्नोलॉजी में बांस का इस्तेमाल करने वाली आर्टिशन दुनिया की पहली कंपनी है। यहां फर्नीचर से घर तक बनाने में बांस काम में लिया जा रहा है। जामगोद स्थित इस कंपनी से बांस के फर्नीचर और गेट और कई तरह के उत्पाद विदेश भेजे जा रहे हैं। कंपनी के सीईओ देवोपम मुखर्जी ने बताया पिछले कई महीनों से अलग-अलग देशों में कटंगा बांस पर रिसर्च चल रहा था। इसी क्रम में डेनमार्क में प्रयोग सफल रहा और कंपनी को मंजूरी मिल गई। इसके तहत अब इंजीनियरिंग प्रोसेस से बांस की पंखुड़ियां बनाई जाएंगी।

महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा

खास बात यह है कि ब्लेड बनाने का काम दो हजार महिलाएं करेंगी। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुखर्जी बताते हैं कि पहले से जिले में हजारों एकड़ भूमि में जंबू बांस का रोपण करा चुके हैं। 50 एकड़ जमीन में एक अलग फैक्टरी का निर्माण भी कराया जाएगा। ब्लेड निर्माण कार्य दो से तीन माह में शुरू हो जाएगा। पदेश में अभी तक पवन चक्की विदेशों से आ रही है, लेकिन बांस की ब्लेड का देश में पहला प्रयोग देवास में किया जा रहा है।

वजन और लागत दोनों कम

पवन ऊर्जा का निर्माण करने में पवन चक्की पर फाइबर की जो ब्लेड लगाई जाती है वह लगभग डेढ़ सौ टन की होती है। लेकिन बांस से बनी ब्लेड का वजन उसके मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत कम होगा। एक पवन चक्की में तीन ब्लेड लगाई जाती हैं जिनकी कीमत 3 करोड़ पड़ती है, लेकिन बांस से बनी यह ब्लड 15 प्रतिशत कम कीमत में तैयार की जाएगी। देश में भी पवन चक्की विदेशों से तैयार होकर आती है, लेकिन अब बांस की ब्लेड का प्रयोग देवास में हो रहा है। ये प्रयोग आगे चलकर देश के लिए लाभदायक साबित होगा।

किसान यहां करें शिकायत, जल्द मिलेगी राहत

अब फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की नहीं होगी टेंशन

भोपाल।

प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान के चलते किसानों को आत्महत्या करने तक को मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब अगर वे समय रहते फसल नुकसान होने की खबर सरकारी तंत्र तक पहुंचा दें तो उन्हें आसानी से मुआवाजे की राशि मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें किसी अधिकारी को रिश्वत भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फसल नुकसान होने पर शिकायत करने के लिए एक कई सारी व्यवस्थाएं कर दी है। कई बार देखा गया है कि किसान जानकारी के अभाव में फसल बर्बाद होने के बाद मुआवजे की मांग नहीं कर पाते हैं। उन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि प्राकृतिक रूप से फसल के नुकसान होने के बाद सरकारी मदद लेने के लिए क्या करना चाहिए।

ऐसे में सुखाड़, बाढ़, या आगजनी से फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि, केंद्र सरकार के साथ- साथ राज्य सरकारें भी फसल बर्बाद होने पर किसानों की मदद के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही हैं।

प्राकृतिक आपदा पर लाभ मिलता था

केंद्र सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत की जाती है। इस योजना की खासियत है कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ- साथ व्यक्तिगत नुकसान होने पर भी किसानों को मुआवजा दिया जाता है। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं में बर्बाद फसलों पर लाभ मिलता था।

यहां करें शिकायत

प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाए, तो ऐसे में किसानों को 72 घंटे के अंदर ही शिकायत दर्ज करना देनी चाहिए। किसान क्रॉप इंश्योरेंस एप पर नुकसान की सूचना दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी जाकर कॉल कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर भी किसान फसल नुकसान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। लेकिन लाभ लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है।

पशुओं में एंथ्रेक्स(गिल्टी) रोग: कारण, देखभाल और बचाव के उपाय

» डॉ. बृजमोहन सिंह धाकड़
» डॉ. रणविजय सिंह
» डॉ. विष्णु गुप्ता
» डॉ. भावना गुप्ता
» डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
» डॉ. अजय राय
» डॉ. रश्मि कुलेश
- पशुचिकत्सा जनस्वास्थय और महामारी विज्ञान विभाग पशुचिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे. प.वि.वि.जबलपुर (मप्र)
- पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तहसील- बरेला, जिला- जबलपुर (मप्र)
- पशु उत्पाद प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर(मप्र)
-पशुसूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग पशु चिकत्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, ना.दे.प.वि.वि. जबलपुर(मप्र)

एंथ्रेक्स (गिल्टी रोग) एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसीस नामक ग्राम-पॉजिटिव, रॉड के आकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। यह प्राकृतिक रूप से मिट्टी में होता है और आमतौर पर दुनिया भर के घरेलू और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आने पर लोग एंथ्रेक्स से बीमार हो सकते हैं। एंथ्रेक्स इंसानों और जानवरों दोनों में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। भारत में, अधिकांश राज्यों से पशु एंथ्रेक्स की सूचना मिली है। यह तमिलनाडु और महाराष्ट्र में व्यापक है, हालांकि, अन्य राज्यों में कुछ स्थानिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। 1981 से 1994 के दौरान इसकी घटना मवेशियों, भेड़, बकरियों और भैंसों में प्रति मिलियन जनसंख्या पर 1.5 से 9.4 तक थी। 1994 में एंथ्रेक्स से प्रभावित भेड़ों और बकरियों की संख्या गायों की तुलना में तीन गुना अधिक थी। हाल के वर्षों में जानवरों में एंथ्रेक्स के कुल मामले बढ़ रहे हैं। **मेजबान रेंज और जलाशय:** घरेलू जानवरों (मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस) के साथ-साथ कई जंगली प्रजातियों सहित शाकाहारी जानवर एंथ्रेक्स के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। सूअर, घोड़े, कुत्ते और ऊंट मध्यम रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं। हालांकि, मांसाहारी और पक्षी आमतौर पर एंथ्रेक्स के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। मनुष्य मध्यम रूप से प्रतिरोधी है। शाकाहारियों में एंथ्रेक्स मुख्य रूप से दूषित चारे/अनुचित संसाधित फीड (मांस भोजन, हड्डी भोजन, मांस स्क्रैप) के अंतर्ग्रहण से फैलता है। और बीजाणुओं के अंत:श्वसन द्वारा भी जो कि फोमाइट्स या हवा द्वारा पर्यावरण में फैल सकते हैं चारे का संदूषण चारागाह भूमि/घास में दूषित पानी से भर जाने, संक्रमित जानवरों/शवों के शरीर के विषाणु से होता है। जानवरों में एंथ्रेक्स के सामान्य लक्षणों में गंभीर म्यूकोसल कंजेशन शामिल हैं, जिसके कारण मुंह, गुदा और नाड़ियों (पैथोग्नोमिक), शरीर का ऊंचा तापमान (मवेशियों में 40-41), डिस्फ़्रेआ, सामान्यीकृत शोफ उत्तेजना या अवसाद, एनोरेक्सिया, ऐंठन, डगमगाने से रक्तावि होता है। चाल, दस्त / पेचिश, गर्भपात, खून से सना हुआ दूध और मार्टिन की अनुपस्थिति शाकाहारी जीवों में, रोग उच्च मृत्यु दर के साथ ज्यादातर अति तीव्र (सेप्टीसीमिया और टॉक्सीमिया के कारण 10-24 घंटों के भीतर अचानक मृत्यु) है। इसे अपोप्लेक्टिक/फुलमिनेंट/प्रति तीव्र रूप कहा जाता है। गैस्ट्रो-आंत्र रूप सबसे आम है। त्वचीय एंथ्रेक्स यांत्रिक वैक्टर के काटने या घाव के संदूषण के माध्यम से हो सकता है, हालांकि, मृत्यु आमतौर पर एस्केर / कार्बुनकल विकसित होने से पहले होती है। मांसाहारियों में, रोग का परिणाम घातक हो सकता है या ठीक हो सकता है।

त्वचीय रूप (घातक फुंसी/एस्चर): यह बीजाणुओं द्वारा कट और घर्षण के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करने के कारण होता है। यह रूप अक्सर आत्म-सीमित होता है और पप्यूले द्वारा विशेषता होता है जो तेजी से परिगलित हो जाता है और बाद में दर्द रहित, काला एस्चर या कार्बुनकल में टूट जाता है जो एक ओडेमेटस क्षेत्र से घिरा होता है। मवाद केवल दूसरी बार संक्रमित होने पर ही मौजूद होता है, हालांकि, उपचार की परवाह किए बिना एस्चर के समाधान में 2-6 सप्ताह लगते हैं। बेसिली घाव के लिए स्थानीयकृत रहती है लेकिन मेनिन्जाइटिस / सेल्युलाइटिस का कारण बन सकती है। क्षेत्रीय लिम्फ नोड का एडेनाइटिस आम है लेकिन लिम्फैंगाइटिस केवल द्वितीयक संक्रमण पर होता है। कोई या हल्का बुखार नहीं देखा जाता है। बुखार (40 डिग्री सेल्सियस), ठंड लगना, सिरदर्द, मितली और एनोरेक्सिया के साथ सेप्टिसीमिक मामलों में जल्दी से सांस की तकलीफ सायनोसिस और मृत्यु से पहले पतन हो जाता है। गैंग्रीन एक सामयिक जटिलता है। अनुपचारित मामलों में, परिणाम घातक है।

पशुओं में रोकथाम और नियंत्रण :

1. टीकाकरण : स्थानिक क्षेत्रों में पशुओं का टीकाकरण स्टर्न वैक्सीन की एकल खुराक के साथ) जीवित बीजाणु युक्त एक टीका और बी. एन्थ्रेसीस के एक विशेष प्रकार से तैयार किए गए टॉक्सोइड का भी उपयोग किया जाता है।

2. उचित शव निपटान : एक एंथ्रेक्स शव को नहीं खोला जाना चाहिए क्योंकि यह होगा, परिवेश को दूषित करते हैं। शव को या तो पूरी तरह जलाकर नष्ट कर देना चाहिए या गहरा दफन (कम से कम 6 फीट निर्जल कैल्शियम ऑक्साइड के मोटे आवरण के नीचे यानी क्विक-लाइम फॉलोइंग) फॉर्मेलिन आदि द्वारा इसकी रासायनिक कीटाणुशोधन)। वह जमीन और क्षेत्र जहां शव पड़ा था। 3प्रतिशत पेरासिटिक एसिड (8 लीटर/मीटर) या 3-5प्रतिशत फॉर्मलाडेहाइड (40 लीटर/शव) के साथ कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

3. पशुधन (रोगग्रस्त/स्थानिक क्षेत्रों से) को संभालने में देखभाल : बीमार पशुओं के शीघ्र निदान और शीघ्र कीमोथेरेपी का प्रयास किया जाना चाहिए। एंथ्रेक्स से पीड़ित होने के संदेह में किसी जानवर के वध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्थानिक क्षेत्र के जानवरों को वध से पहले या नए जानवरों के साथ मिलाने से पहले छोड़ दिया जाना चाहिए। घाव की ड्रेसिंग कीटाणुरहित उपकरणों और साफ हाथों से की जानी चाहिए। त्वचीय घाव वाले व्यक्तियों को पशुओं और उनके चारे/चारे को नहीं संभालना चाहिए।

इसी रबी सीजन से शुरू होगी जीएम सरसों की बोवनी, सामान्य सरसों के मुकाबले 28 फीसदी की वृद्धि दर्ज की

बीज उत्पादन के लिए 100 स्थानों का आईसीएआर ने किया चयन

तीन वर्षों तक किया जीएम सरसों की उपज का अध्ययन

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर सांइसेज (एनएएएस) और एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सांइसेज ट्रस्ट (टीईएएस) के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों की खेती इसी रबी सीजन में शुरू करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है। जल्द ही 100 से अधिक स्थानों पर जीएम सरसों के बीज उत्पादन के लिए बोवनी की जाएगी। इस कार्य योजना का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) करेगा। वैज्ञानिकों की दोनों संस्थाओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि अत्यंत आनुवांशिकी इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) ने सरसों की हाइब्रिड को पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड का पेटेंट वैज्ञानिक दीपक पेंटल के पास है। यह पर्याप्त प्रमाण है कि बिना किसी देरी के अब इस उन्नतशील किस्म की बुवाई की जा सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि पर्यावरण रिलीज की मंजूरी पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नहीं बल्कि जीईएसी ने दी है।

उपयोग

एनएएएस के अध्यक्ष टी महापात्रा ने कहा है कि वर्तमान में जीएम-डीएमएच-11 सरसों के लगभग 11 किलो बीज उपलब्ध हैं। इसमें से 2 किलोग्राम बीज का भरतपुर के आईसीएआर के रेपसीड और सरसों निदेशालय अध्ययन कर रहा है। चालू रबी सीजन में सरसों की बुवाई का समय अगले 10-15 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमने स्थानों का चयन कर लिया है और बोवनी के लिए तैयारियां तेज कर रहे हैं। अगर हालात सामान्य रहे तो अगले तीन सालों में जीएम सरसों किसानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

शहद उत्पादन के लिए नहीं खतरनाक

जीएम सरसों के लाभों पर, टीएस महापात्रा और आरएस परोदा ने कहा कि आईसीएआर भरतपुर की देखरेख में आठ स्थानों पर तीन वर्षों तक जीएम सरसों की उपज का अध्ययन किया गया, सामान्य सरसों के मुकाबले इसकी उपज में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एनएएएस के सचिव केसी बंसल ने कहा कि इससे न तो मधुमक्खियों को खतरा है न ही परागकण को, फैलाई जा रही सूचनाएं भ्रामक हैं।

देश का सर्वाधिक मसूर उत्पादक राज्य मध्यप्रदेश

किसानों के लिए फायदेमंद मसूर की उन्नत खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

दलहनी फसलों में मसूर का महत्वपूर्ण स्थान है। कम लागत में मसूर की खेती अधिक आमदनी देती है। इसकी खेती में पानी की भी जरूरत बहुत ही कम होती है। कृषि विशेषज्ञों का मत है कि बेहतर खाद प्रबंधन, खेत की तैयारी-खरपतवार नियंत्रण और बीज बोवनी की सही विधि का प्रयोग कर किसान मसूर की बढ़िया उपज प्राप्त कर सकते हैं। मसूर की खेती कम वर्षा और विपरीत परस्थितियों वाली जलवायु में भी सफलता पूर्वक की जा सकती है। देश में मसूर की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सर्वाधिक की जाती है। हमारे देश में मसूर की कई उन्नत विकसित हो चुकी है। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर संपर्क करें। वहां आपको सब्सिडी पर बीज उपलब्ध हो सकता है। मसूर की उन्नत किस्मों में एलएल 699, जेएल- 3, जेएल-1, आईपीएल-81, एल.4594, मल्लिका, पन्त 4076, सीहोर 74-3 प्रमुख हैं।

मसूर की खेती के लिए दोमट या नमी सोखने वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान ऊसरीली या क्षारीय भूमि में मसूर खेती बिल्कुल भी न करें। खरीफ फसलों की कटाई के बाद किसान हैरो या देशी हल से खेत की जोताई कर दें। जोताई के बाद अब इसमें पानी लगाकर खेत को सूखने दें। इसके बाद खेत को रोटावेटर की सहायता से 2-3 बार क्रॉस जोताई करें। 24-48 घंटे बाद खेत में पाटा लगा दें। समतल खेत में ही बीज की बुवाई करें। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि भरपूर उपज के लिए किसान सामान्य मात्रा 30-35 किग्रा बीज से 1.5 गुना अधिक बीज की बोवनी प्रति हेक्टेयर करें। बीज बोवनी के दौरान पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20-30 सेंटीमीटर रखें। कृषि विशेषज्ञ बीज बोवनी के लिए संध्या काल उचित माना जाता है।

खाद एवं उर्वरक का प्रयोग

मसूर की बढ़िया पैदावार प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक के तौर पर 40 किग्रा फास्फोरस, 15-20 किग्रा नाइट्रोजन, 20 किग्रा पोटाश और 20 किग्रा सल्फर का प्रति हेक्टेयर छिड़काव बीज बोवनी के समय करें। असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की 50 प्रतिशत मात्रा का छिड़काव बुवाई के समय करें। यदि भूमि में जस्ता (जिंक) की प्रचुरता कम है तो 25 किग्रा जिंक सल्फेट का प्रयोग बताई गई उर्वरकों के साथ करें।

दो बार करें सिंचाई

मसूर के बीज कम नमी में भी अंकुरित हो सकते हैं। पौधों की बढ़िया वृद्धि के लिए 1 या 2 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती हैं। पहली सिंचाई 30-40 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई फली में दाना पड़ते समय करना लाभदायक होता है। किसान सिंचाई के लिए स्प्रिंकल विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के समय खेत में पानी जमा न होने दें।

रोग एवं कीट प्रबंधन

मसूर की फसल में रोग ना लगें इसके लिए फसल की निराई-गुड़ाई अति आवश्यक है। फसल में खरपतवार की उपलब्धता अनुसार बोवनी के 20-25 दिन व 40-45 दिन बाद निराई-गुड़ाई, खुरपी या डोरा चलाकर कर लें। खरपतवार के रसायनिक नियंत्रण के लिए पेन्डी-मिथेलिन या फ्लूक्लोरोलिन 0.75 किलो ग्राम को 500 लीटर पानी में मिलाकर एक हेक्टेयर में घोलकर छिड़काव कर मिट्टी में मिलाने से खरपतवारों के प्रकोप से बचा जा सकता है।

-केंद्र सरकार के प्रयास से कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

एथेनॉल कीमतें, फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी हुआ इजाफा

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं गए हैं। पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की राशि को भी बढ़ाया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने सी हैवी मोलासेज की कीमत 46.66 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 49.41 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। जबकि, बी हैवी मोलासेज का दाम 59.08 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा कर 60.73 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी तरह गन्ने के रस से बनने वाले इथेनॉल की कीमत 63.45 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 65.61 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी और परिवहन शुल्क भी लगाया गया है।

2030 में पूरा करने का लक्ष्य - केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सीसीइए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए साल 2005 से ही कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में पेट्रोल में 1.4 प्रतिशत ब्लेंडिंग थी। एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20 प्रतिशत टारगेट को पूरा करने का समय अवधि घटा दिया गया है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के 20 प्रतिशत टारगेट को 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। पहले इसे 2030 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से सभी डिस्टेलरी इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। वहीं, इथेनॉल की सप्लाई ईबीपी कार्यक्रमों के लिए भी किया जा सकेगा। साथ ही सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों को भी काफी फायदा होगा। किसानों को अब जल्द भुगतान करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10 प्रतिशत तक बेचती हैं।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से मिलेगा कृषि को बढ़ावा

वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग विस्तार करना चाहती है। केंद्र सरकार ने ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है।

जबलपुर संभाग में होती है सबसे ज्यादा रकबे में खेती

एक साल में 129 प्रतिशत तक बढ़ गई मोटे अनाज की डिमांड

प्रवीण नामदेव। जबलपुर

राज्य सरकार के प्रयासों और बढ़ती मांग के चलते मोटे अनाज (मिलेट्स) के दिन फिर बहुरने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो में मोटे-अनाज का जिक्र करके लोगों का ध्यान एकाएक इस ओर खींचा था। उन्होंने कहा था कि मोटा अनाज हमारी परंपरा और प्रकृति से जुड़ा है, इसलिए किसानों को इसका उत्पादन बढ़-चढ़कर करना चाहिए। इनकी मांग महज एक साल के दौरान ही 129 प्रतिशत बढ़ चुकी है। खपत बढ़ने से किसानों ने खेती का रकबा भी बढ़ाया। रकबे में 116 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। खास बात यह है कि तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों ने उपज का अनुपात बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है उसका तीन चौथाई रकबा जबलपुर संभाग का है। इन फसलों की ओर किसानों का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा। वह गेहूं, चावल, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन में ही लाभ की संभावनाएं देखते हुए उनका उत्पादन करते रहे। बीते कुछ वर्षों के दौरान मोटे अनाज के प्रति न केवल किसानों का रुझान बढ़ा है, अपितु महाकोशल में उसके कारोबार में भी वृद्धि देखने का मिली है। बीते पांच सालों के दौरान इसका बाजार पांच गुना हो चुका है।

चार जिले बने प्रमुख केंद्र

मोटा अनाज में प्रमुख रूप से जिन उत्पादों को रखा गया है, उनमें कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सांबा, रागी, मक्का आदि हैं। महाकोशल में इनमें से कोदो, कुटकी को प्रमुखता से लिया जा रहा है। ज्वार, बाजरा भी इस क्षेत्र में होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। महाकोशल में कोदो-कुटकी की फसल मुख्यत: मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और जबलपुर के कुंडम में होती है। मोटे अनाज में पौष्टिकता होने के साथ ही अनेक प्रकार के खाद्य-औषधीय गुण भी हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी फायदेमंद हैं। मोटे अनाज में कैल्शियम आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम, विटामिन बी-6 और विटामिन बी-3 पाया जाता है। विशेषत: महाकोशल में होने वाले कोदो-कुटकी में शुगर, किडनी और ब्लडप्रेशर से राहत दिलाने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं।

सीधे किसानों से खरीद लेते हैं उपज

जबलपुर की एमओ-मंडला समूह की ओर से न केवल जबलपुर संभाग बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों से भी किसानों से सीधे संपर्क करके उनसे मोटे अनाज की खरीदी की जा रही है। इसके लिए संगठन की ओर से इनका उत्पादन करने वाले जिलों में अपनी टीमें बनाई गई हैं, जो सीधे किसानों से संपर्क कर उपज को खरीदती हैं। इसके अलावा जबलपुर में ही सहकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रियदर्शनी सोसायटी में भी मोट अनाज का विक्रय किया जाता है।

लगातार हो रहा इजाफा

महाकोशल क्षेत्र में मोटे अनाज का क्रय-विक्रय करने वाली संस्था एमओ-मंडला के डायरेक्टर शांत चड्ढा ने बताया कि जबलपुर क्षेत्र में मिलेट्स का उत्पादन और विक्रय में लगातार इजाफा हुआ है। वर्ष 2018 में उनके संगठन ने डेढ़ टन मिलेट्स की आपूर्ति की। जो 2019 में बढ़कर साढ़े तीन टन, 2020 में पांच टन, 2021 में साढ़े आठ टन और 2022 में 11 टन हो गई।

सबसे महंगे अनाजों में शुमार

मिलेट्स को एक समय कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब से उसके गुणों के बारे में लोगों को पता चला तो दाम आसमान पर चले गए। आज कोदो-कुटकी और ज्वार सबसे महंगे अनाजों में शुमार हैं। कोदो-कुटकी का बाजार मूल्य 150 रुपये प्रति किलो है, जबकि ज्वार 110 रुपये किलो है। अनाजों में सबसे महंगी सफेद (पीली) मूंग 120 रुपये किलो है। शहर में पहले मिलेट्स को कोई नहीं पूछता था। लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान कोदो-कुटकी, ज्वार, बाजरा की मांग में वृद्धि हुई है। बीते तीन वर्षों के दौरान मांग में ढाई गुना तक इजाफा हो चुका है।

एमके बहरे, प्रियदर्शनी सहकारिता समिति

मोटे अनाज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसी कड़ी में इसकी खेती का रकबा बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, मूल्य संवर्धन और उसकी पैकेजिंग-ब्रांडिंग की योजनाएं बन रही हैं।
-डॉ. केएस नेताम, जेडी कृषि

संभाग में बीते दो साल के दौरान

मोटा अनाज का नाम	2021 - कुल रकबा	2022 - कुल रकबा	उत्पादकता 2021 - किलो प्रति हैक्टे.	उत्पादकता 2022 - किलो प्रति हेक्टेयर
कोदो-कुटकी	87700 हेक्टेयर	101900 हेक्टेयर	859	904
ज्वार	5500 हेक्टेयर	6800 हेक्टेयर	2252	2271

बैतूल उद्यानिकी विभाग ने फूड प्रोसेसिंग के लिए आवेदन

14 इकाइयों के लिए मांगी एप्लिकेशन, 35 फीसदी तक अनुदान

सतीष साहू। बैतूल

14 से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए उद्यानिकी विभाग ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना है। इस योजना में हितग्राही को अनुदान भी दिया जाएगा। भाणगाणा न फूड प्रोसेसिंग के लिए जैसे- आम का अचार, जैम, जैली, पापड़, मसाला सूक्ष्म उद्योग, सोयाबड़ी, राइस मिल, ऑइल मिल, दाल मिल, गुड़घानी, आलू चिप्स, मुरब्बा, सॉस एवं कैचप इत्यादि स्थापित कराने के लिए प्रत्येक उद्योग पात्रता परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक पूंजी सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए दी जाएगी। लाभार्थी का योगदान लगभग 10 प्रतिशत रहेगा।

शैक्षणिक योग्यता

उक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास एवं उम्र 18-60 वर्ष होनी अनिवार्य है। आवेदक के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ प्राप्त से होगा।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवदेन के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, मार्क शीट, कोटेशन मशीनरी, इनकम टैक्स रिटर्न- तीन साल (यदि उपलब्ध है), यूनिट की जगह के दस्तावेज- रजिस्ट्री/खसरा की छायाप्रति, डायवर्सन की कॉपी/ऑनलाइन आवेदन की रसीद, यूनिट का प्रमाणित नक्शा, दोनों बैंकों की पासबुक की छायाप्रति, बिजली का बिल, यदि पुराना उद्यम है तब ऑडिट बैलेंस शीट (तीन वर्ष की), यदि पूर्व का कोई लोन है तो लोन स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने का), संस्था का पंजीयन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन (यदि उपलब्ध हो), प्रस्तावित यूनिट की जगह का फोटो एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक उद्यान बैतूल एवं योजना के पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है। दिशा-निर्देशानुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं वाइबल डीपीआर अपलोड कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

-इंदौर में पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन का उठा रहे लाभ

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना 35 फीसदी अनुदान

इंदौर। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत इंदौर जिले के युवा शिक्षित बेरोजगार/किसान भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी है। इस योजना में प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपए तक की अनुदान सहायता दी जाती है।

योजना की पात्रता - आवेदकों के पास स्वयं का भू-स्वामित्व अधिकार होना अनिवार्य है। एक परिवार के एक व्यक्ति को ही लाभ प्राप्त होगा। यह योजना नए उद्योग स्थापित करने, पूर्व से स्थापित सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के उन्नयन में सहायता के लिए है। इसमें इसके की लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंकड अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो अधिकतम 10 लाख रुपए होगी।

इन इकाइयों पर अनुदान मिलेगा

योजना अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां जैसे आलू से निर्मित खाद्य पदार्थ, चिप्स,पाउडर, फ्लेक्स स्टार्च आदि। इसके अलावा लहसुन एवं प्याज पेस्ट, पाउडर, अन्य उत्पाद टमाटर कैच अप, अचार, पापड़, मुरब्बा, ज्यूस, चॉकलेट, बेकरी, मसाला, नमकीन, सोयाबीन खाद्य पदार्थ इत्यादि। इस योजना में नवीन उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व से स्थापित इकाइयों के उन्नयन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग के सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। खरगोन जिले में आगामी दिनों में ओडीओपी अर्थात एक जिला एक उत्पाद दिवस कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाएगा। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित मशीनरी की प्रदर्शनी, बैंकर्स एवं डीआरपी के काउंटर, योजना के साहित्य, मॉडल डीपीआर, पम्पलेट, उद्यानिकी उत्पाद एवं प्रसंस्कृत उत्पादों की सजीव प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

आवेदन ऑनलाइन करना होगा। सीए द्वारा रिपोर्ट बनेगी। 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा करनी होगी। 10 लाख तक का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इससे अधिक का भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सब्सिडी 10 लाख तक ही होगी। प्रोजेक्ट मशीनों की लागत पर होगा न कि गोदाम/स्थान आदि का। अंतिम तिथि अभी तय नहीं है। यह योजना अभी चल रही है। इच्छुक व्यक्ति इस अवसर का लाभ ले सकते हैं।

ओमप्रकाश ठाकुर, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, देपालपुर

गांव की साफ-सफाई के लिए पंचायत वसूलेगी टैक्स, सतना की बड़ा एटमा पंचायत में हर महीने देना होगा 10 रुपए

मप्र में पहली बार सतना की पंचायत ने शुरू किया स्वच्छता कर

भोपाल। जागत गांव हमार

सतना जिले की बड़ा एटमा पंचायत ने बड़ा काम किया है। पंचायत ने फैसला किया है कि अब घर से स्वच्छता कर वसूला जाएगा। ये सिर्फ 10 रुपए प्रति घर होगा लेकिन इससे गांव में साफ सफाई का बड़ा काम होगा। स्वच्छता कर लगाने वाली ये प्रदेश के पहली पंचायत हो गयी है। जिले की बड़ा एटमा पंचायत जिले की पहली पंचायत बन गयी है जो अब स्वनिधि के तहत पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर लगा रही है। इस कर का इस्तेमाल वो अपने पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई और हरियाली के लिए करेगी। 75 वर्षीय महिला सरपंच गीता पांडेय ने ग्राम सभा में सर्व सम्मति से स्वच्छता कर लगाने का निर्णय लिया है। हर परिवार से 10 रुपए हर माह स्वच्छता कर वसूला जाएगा। यह व्यवस्था एक नवम्बर से शुरू हो गई है। पंचायत का स्वयं का कचरा वाहन है, जो हर घर से कचरा इकट्ठा कर रहा है। इसके साथ ही हर वर्ष पंचायत में एक हजार पेड़ लगाने का भी फैसला लिया गया।

महिला सरपंच का बड़ा फैसला

सतना जिले के रामनगर जनपद की ग्राम पंचायत बड़ा एटमा की विशेष सभा में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा निर्णय लिया गया। महिला सरपंच गीता पांडेय ने विशेष ग्राम सभा की और पंचायत के विकास से कई अहम निर्णय लिए। ये प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुए। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाली गीता पण्डेय ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पारदर्शी स्थानीय सरकार का संकल्प लिया।

मांस विक्रय के लिए जगह तय

साथ ही गांव में मांस व्यापार के लिये मध्यप्रदेश मांस विक्रय नियम के अंतर्गत जगह तय कर दी। उसके सिवाय कहीं और मांस बेचने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पेय जल वितरण के रूप में ली जाने वाली राशि में पूरी पार्दर्शिता का संकल्प पारित किया गया। सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को पंचायत में जन सुनवाई और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1000 पौधरोपण करने का संकल्प लिया गया। पंचायत को स्वच्छता कर से जो आमदनी होगी उसका इस्तेमाल कचरा वाहन, कचड़ा पेटी, गंदे जल का फिल्टर प्रबंधन और पानी निकासी की व्यवस्था के लिए किया जाएगा।

30 प्रतिशत ज्यादा होगी पैदावार, दो सिंचाई में फसल हो जाएगी तैयार

वैज्ञानिकों ने विकसित किया मटर का उन्नत बीज

भोपाल/कानपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञानियों ने मटर के ऐसे उन्नत किस्म का बीज विकसित किया है, जो 30 के बजाए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी भरपूर उत्पादन देगा। यही नहीं, स्टोर कर रख देने पर भी इस मटर का रंग हरा रहेगा और स्वाद ताजा मटर जैसा ही होगा। विज्ञानियों ने इस प्रजाति की पैदावार अन्य मटर के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक होने का दावा किया है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के कृषि विज्ञानी डॉ. अशोक परिहार और डॉ. जेपी दीक्षित ने नई किस्म तैयार की है, जिसका नाम आइपीएफडी 10-12 रखा गया है। इस नई किस्म को तैयार करने में करीब दस साल लगे हैं। कृषि विज्ञानियों का कहना है आईपीएफडी 10-12 बीज से उत्तर भारत में मटर का उत्पादन 30 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। यूपी के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और मप्र के ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी आदि के किसान इसका उत्पादन करने में रुचि दिखा रहे हैं। इस बीज के दाने में मिठास कम रहने से मधुमेह रोगी भी इसका स्वाद ले सकेंगे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि के डायरेक्टर आफ रिसर्च संजय शर्मा का कहना है कि बीज को बढ़ावा देने के लिए दतिया, भिंड व ग्वालियर के किसानों को बीज की उपलब्धता कराई गई है।

दाने का नहीं बदलेगा रंग

रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विवि झांसी के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सुशील चतुर्वेदी का कहना है कि इस बीज से तैयार मटर का दाना सूखने पर रंग नहीं बदलता। सूखी मटर को कोल्ड स्टोर में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान अब खुद हरी मटर को डिब्बा पैक कर बाजार में ऊंचे दाम पर बेच सकेंगे।

आइपीएफडी 10-12 किस्म की पैदावर आम मटर की प्रजाति से डेढ़ गुना अधिक है। मिठास कम होने के साथ इसका दाना सूखने के बाद भी हरा व गोल रहेगा। उत्तर भारत में इसकी पैदावार पिछले बीजों से 30 प्रतिशत अधिक होगी। किसान अब हर मौसम में मटर के हरे दाने छोटे पैकेट बनाकर बाजार में बेच सकेंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी।

डॉ. एसके चतुर्वेदी, कृषि वैज्ञानिक

120 से 125 दिन में तैयार होगी फसल

डॉ. चतुर्वेदी का कहना है मटर की फसल 120 से 125 दिन में तैयार होगी। वर्तमान मटर की फसल के लिए एक बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि इस नई किस्म में दो पानी दिया जाता है। इसकी बोवनी 10 नवंबर तक होनी चाहिए, जिससे इसकी पैदावार बेहतर होती है। 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। इसमें डाई अमोनियम सल्फेट की खाद देने की आवश्यकता होती है, जिससे पैदावार 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। इसकी फलियां तोड़कर सब्जी के लिए बेची जा सकती हैं।

शिवपुरी में लगा जैविक हाट

शिवपुरी। खेमराज मौर्य, जागत गांव हमार

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शनिवार को जैविक हाट बाजार का आयोजन शासकीय पौधशाला शिवपुरी के कृषक प्रशिक्षण भवन में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह चंदेल उपस्थित थे। जैविक हाट बाजार के आयोजन में जिले के जैविक एवं प्राकृतिक तरीकों से उत्पादित फल, सब्जियों एवं फूलों तथा वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि का प्रदर्शन कृषकों द्वारा किया गया। जिले के उपसंचालक कृषि यू.एस. तोमर, कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.एम.के.भार्गव ने प्राकृतिक कृषि प्रोत्साहन की जानकारी देते हुए जिले के कृषकों को कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक कृषि अपनाने का अनुरोध किया। प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कृषकों एवं उत्पादकों द्वारा अपने विचार रखे गये। जिसमें शिवपुरी से रामगुत्ता , हाकिम सिंह नरवर, गालमसिंह बदरवास, शिवपुरी के अनिकेत धाकड़, दिलीप धाकड द्वारा अपने विचार रखते हुए सफलता की बारीकियों को बतलाया। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कृषकों को प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी। उन्होंने कृषकों से कहा कि जैविक खेती में पंजीयन कराएं। खेती को लाभ का धंधा बनाएं और अपने पैरों पर खड़े हो। उन्होंने किसानों से कहा कि संगठन बनाकर बड़े स्तर पर मूंगफली की ग्रेडिंग, टमाटर सॉस, आटा चक्की उद्योग लगाकर लाभ कमाएं और आर्थिक रूप से सक्षम बनें। उद्यानिकी विभाग के मैदानी अधिकारी एवं एस.एस. कुशवाह, सहायक संचालक उद्यान ने कृषकों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उद्यानिकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

आदिवासी संस्कृति से परिचित हो सकेंगे पर्यटक

खजुराहो में बसाया जा रहा जनजातीय गांव

छतरपुर। जागत गांव हमार

खजुराहो आने वाले देशी-विदेशी सैलानी प्रदेश के आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, जीवनशैली से परिचित होंगे। इसके लिए खजुराहो के आदिवर्त जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय परिसर में आदिवासी गांव बसाया है। यहां मप्र के आदिवासियों की सात जनजातियों को बसाया जा रहा है। कोरकू, बेगा, गौड़ और भारिया जनजाति के परिवार आकर बस गए हैं। इन आदिवासियों ने अपने पारंपरिक घरों को खुद लीप-पोत कर तैयार किया है। शेष अन्य जनजातियों को भी यहां जल्द लाया जाएगा।

जनजाति लोककला राज्य संग्रहालय खजुराहो के प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार यह गांव बसाया है। ऐसे में खजुराहो आने वाले पर्यटक एक ही स्थान पर मप्र की जनजातियों की संस्कृति एवं उनके रहन-सहन से परिचित हो सकेंगे। मध्यप्रदेश की कोल, भील, गौंड, बैगा, भारिया, कोरकू एवं सहारिया जनजाति के परिवार इस बस्ती में अपनी प्राचीन जीवन शैली के साथ रहेंगी। इस बस्ती में एक चौपरा भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें यह आदिवासी परिवार स्नान आदि करेंगे।

पांच जनपदों से बुलाए परिवार

अशोक मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश की सात लोक जनजातियों के अलावा राज्य के पांच जनपदों बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ एवं चंबल के लोक समुदायों की संस्कृति एवं विशिष्टता को भी यहां प्रदर्शित किया जाएगा।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)